Statement—I

StaluS of progress made for various types of non-conventional energy systems & devices

S. No.	Programme	Units	Cumulative Achievement upto 31.12.91
18.	Biomass Stirling Engines	Nos.	100

Statement—II

Performance of IREDA during last three years

	1988-89	1989-90	1990-91
A. RESOURCES			
Equity Capital Allocation released during the year (Rs. lakhs)	250.00	325.00	—
Borrowing from Market (Rs. lakhs)	—	—	2500.00
Grant-in-aid received from the Govt. of the Netherlands during the year (Rs. lakhs)	466.60	302.90	—
B. SANCTIONS			
No. of Projects	20	31	55
Loan amount (Rs. lakhs)	416.56	582.87	2629.35
C. DISBURSEMENTS			
Nos. of Projects	20	28	40
Amount (Rs. lakhs)	465.75	491.59	822.92
D. RECOVERY (% of Recoveries to total dues)	100%	94.5%	92.6%
E. PROFIT BEFORE TAX (Rs. lakhs)	47.69	79.70	124.39

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान का कार्यकरण

3492. **श्री महेन्द्र सिंह लाठर:** क्या **विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में लगातार घाटे बढ़ते जा रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस संस्थान में बिजली के पारेषण और वितरण में नुकसान भी बढ़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो इस संस्थान में वर्ष 1985 से बढ़ते हुए घाटे का वर्षवार ब्यौरा क्या है और सरकार ने उसके घाटों को कम करने तथा बिजली के पारेषण और वितरण में होने वाले नुकसान को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की है और इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) दिल्ली में चालू वर्ष के दौरान बिजली की अनुमानित आवश्यकता कितनी है और इसका कुल उत्पादन कितना है?

विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) से (ग)

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान मुख्यतः अलाभकारी टैरिफ के कारण राजस्व घाटे की स्थिति का सामना कर रहा है। इसकी वर्षवार हानियों का ब्यौरा निम्नवत है:—

वर्ष	हानि (करोड़ रु० में)
1985-86	15.09
1986-87	64.08
1987-88	178.62
1988-89	174.79
1989-90 (अनन्तिम)	233.29
1990-91 (अनन्तिम)	200.09

वित्तीय स्थिति में सुधार किए जाने की दृष्टि से दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने 1.3.1991 से अपनी टैरिफ में संशोधन किया है। उठाए गए विभिन्न कदमों के परिणामस्वरूप, जिनमें ऊर्जा की चोरी के विरुद्ध व्यापक अभियान चलाना भी शामिल है, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने सूचित किया है कि पारेषण एवं वितरण संबंधी हानियों की मात्रा जोकि 1987-88 में 30.78% थी 1990-91 में घटकर 19.68% हो गई है।

(घ) चालू वर्ष के दौरान दिल्ली को लगभग 800 मिलियन यूनिट ऊर्जा की आवश्यकता है जिसमें से दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अपने स्रोतों से विद्युत उत्पादन की मात्रा लगभग 200 मिलियन यूनिट है। शेष विद्युत बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र तथा अन्य बाह्य स्रोतों से खरीदी जाती है।

उत्तर प्रदेश में जलधारा योजना

3493. **श्री ईश दत्त यादव:** क्या **विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में "जलधारा योजना" के अन्तर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान इन लक्ष्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया जा सका है; और

(ग) इस संबंध में इस राज्य में आगामी वर्ष के लिए किए गए प्रावधानों का जिलावार ब्यौरा क्या है?

विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) से (ग) 13 राज्यों के अभिज्ञात किए गए सूखा प्रणत क्षेत्रों में छोटे किसानों को पम्पसैट उपलब्ध करवाने के लिए 1988-89 में भारत सरकार द्वारा एक-कालिक उपाय के रूप में "जलधारा योजना" शुरू की गई थी। यद्यपि, उत्तर प्रदेश के लिए इस स्कीम के अन्तर्गत 7,073 पम्पसैटों के लक्ष्य का प्रस्ताव था, किन्तु राज्य द्वारा इस स्कीम को हाथ में नहीं लिया गया था। यह स्कीम अब लागू नहीं है।

Shortage of coal at Raichur Thermal Power Project

3494. SHRI B.K. HARIPRASAD: Will the Minister of POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES be pleased to state:

(a) whether Government have received representation from Karnataka Chief Minister in respect of shortage of coal at Raichur Thermal Power Project: and

(b) if so. details thereof indicating the corrective action taken or proposed to be taken to ensure adequate generation of power supply for industries?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI KALP NATH RAI): (a) Yes, Sir.

(b) Coal supply to various thermal power stations, including Raichur Thermal Power Station, is being regularly reviewed by a High Level Committee. Coal linkage to Raichur Thermal Power Station has been increased to 31500 tonnes per month since October. 1991. Power supply to various categories of consumers, including industries, is regulated by the respective State Government/State Electricity Board, depending upon the requirement and availability of power.

15 Point Programme for the Welfare of Minorities

3495. SHRI MOHAMMED AFZAL alias MEEM AFZAL: Will the Minister of POWER AND NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES be pleased to state:

(a) whether there are any committee in his Ministry for monitoring Implementation of the 15 Point Programme for the welfare of the Minorities; and

(b) if so, what are the details with regard to such Committee in the Ministry and the number of persons who have been provided with employment during